Times of India, Hyderabad, 09/05/2026
Page No: 3, Size: 17.57cm × 25.96cm

Food delivery worker alleges police assault

Mahesh.Buddi
@timesofindia.com

Hyderabad: The Telangana Gig and Platform Workers Union (TGPWU) has written to the National Human Rights Commission of India (NHRC) after CCTV footage showing Ramgopalpet police allegedly assaulting a delivery worker for a quick-commerce platform during the early hours of Thursday surfaced online.

In a letter addressed to NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian, TGPWU founder-president SK Salauddin alleged that Hyderabad police assaulted and harassed delivery worker Shabbir Azam, a resident of Falaknuma, at around 2.50 am on May 7, when he waiting to pick up an ice cream order from a store in Secunderabad.

UNION WRITES TO NHRC

According to the complaint, two constables from Ramgopalpet police station instructed the delivery workers to leave. "When Shabbir Azam attempted to show the order details assigned through the app, Ramgopalpet police station SHO physically assaulted him. The shop manager, Rahil Hussain, tried to explain that the store had permission to operate in late hours. However, he too was beaten up by the SHO," Salauddin stated in the complaint to the NHRC.

Ramgopalpet inspector B Suresh Kumar told **TOI** that the permission for the store to operate till the early hours had expired in 2024. "I was on night patrol and found the shop delivering orders even after 3 am. One of the persons standing outside the shop, who was not in uniform, responded in an objectionable manner when asked to leave and created a nuisance. I had to use mild force to disperse him," he added.

Mahankali police filed two cases against Azam and Rahil.

Prabhat Khabar, Ranchi, 09/05/2026
Page No: 11, Size: 6.54cm × 16.43cm

देवघर के संप्रेक्षण गृह में मौतों पर मानवाधिकार आयोग सख्त मुख्य सचिव व एसपी को नोटिस

देवघर. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह सह संप्रेक्षण गृह में लगातार हो रही लड़कियों की मौत के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और देवघर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने दो मई को चरकीपहाड़ी स्थित रिमांड होम में 19 वर्षीय महिला कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को गंभीरता से लिया है. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आयोग ने कहा है कि एक जनवरी 2026 से अब तक इस रिमांड होम में पांच लड़कियों की मौत हो चुकी है, जिससे वहां की सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चार मई 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि एक महिला कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद रिमांड होम के कर्मचारियों ने उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. आयोग ने कहा है कि मृतका की मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है. एनएचआरसी ने अपने आदेश में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्य यदि सही पाये जाते हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला माना जायेगा. इसी आधार पर आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और देवघर एसपी को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

Prabhat Khabar, Deogarh, 09/05/2026
Page No: 1, Size: 18.41cm × 19.00cm

देवघर संप्रेक्षण गृह में लड़कियों की मौत पर मानवाधिकार आयोग सख्त, राज्य के मुख्य सचिव व एसपी को नोटिस

इंपैक्ट

वरीय संवाददाता, देवघर

एनएचआरसी ने संप्रेक्षण गृह मामले का लिया स्वतः संज्ञान

- राज्य के मुख्य सचिव व देवघर एसपी से दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी
- दो मई को 19 वर्षीय कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत
- जनवरी से अब तक पांच लड़कियों की मौत से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह सह संप्रेक्षण गृह में लगातार हो रही लड़कियों की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और देवघर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने दो मई को चरकीपहाड़ी स्थित रिमांड होम में 19 वर्षीय महिला कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को गंभीरता से लिया है. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आयोग ने कहा है कि एक जनवरी 2026 से अब तक इस रिमांड होम में पांच लड़कियों की मौत हो चुकी है, जिससे वहां की सुरक्षा और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,

बाकी पेज 09 पर

छह किशोरियों की बिगड़ी तबीयत, तीन सदर अस्पताल में भर्ती

देवघर. कुंडा थाना क्षेत्र स्थित संप्रेक्षण गृह की छह किशोरियों की तबीयत फिर बिगड़ गयी है. इनमें से तीन किशोरियों को गुरुवार रात करीब 10:15 बजे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि तीन किशोरियों का इलाज देवघर एम्स में चल रहा है. एम्स में भर्ती एक किशोरी की हालत गंभीर बतायी जा रही है. जानकारी के अनुसार, गंभीर रूप से बीमार किशोरी को टीबी होने की बात सामने आ रही है. हालांकि मामले में संप्रेक्षण गृह की अधीक्षक सरिता भारती की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गयी है. सदर अस्पताल में भर्ती किशोरियों में एक छह वर्षीय बच्ची बोल नहीं पाती है, जिसे अज्ञात बताकर भर्ती कराया गया है. चिकित्सकों ने बताया कि 13 वर्षीय बड़ी बच्ची का प्लेटलेट्स कम है, जबकि 12 वर्षीय बच्ची एनीमिया व मानसिक बीमारी से पीड़ित है. डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल किसी भी बच्ची में मेजर इलनेस नहीं पाया गया है. रूटीन चेकअप व ऑब्जर्वेशन के तहत तीनों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. बच्चियों के खून समेत अन्य जांच कराये जा रहे हैं.

देवघर संप्रेक्षण गृह में लड़कियों की मौत पर...

चार मई 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि एक महिला कैदी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद रिमांड होम के कर्मचारियों ने उसे इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. आयोग ने कहा है कि मृतका की मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है. एनएचआरसी ने अपने आदेश में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्य यदि सही पाये जाते हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला माना जायेगा. इसी आधार पर आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और देवघर एसपी को नोटिस जारी कर मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. आयोग ने रिपोर्ट में मौत की परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधा तथा अब तक उठाये गये प्रशासनिक कदमों की जानकारी मांगी है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उप निदेशक (मीडिया एवं संचार) जैमिनी कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि रिमांड होम में लगातार हो रही मौतों ने वहां की व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. आयोग ने राज्य प्रशासन से मामले की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है.

Hindustan, Dehradun, 09/05/2026
Page No: 2, Size: 14.61cm × 17.67cm

किशोरी का वीडियो वायरल बाल आयोग ने मांगी रिपोर्ट

देहरादून,वरिष्ठ संवाददाता। हाल ही में एनसीआरबी से जारी आंकड़ों को लेकर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने चिंता जताई। चम्पावत प्रकरण में सम्बन्धित विभागों और जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि बाल अपराधों में वृद्धि के पीछे एक ओर जहां रिपोर्टिंग में तेजी है, वहीं सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का दुरुपयोग भी जिम्मेदार है।

उन्होंने चम्पावत में राजनीतिक रंजिश के चलते नाबालिग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने को कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत किसी भी नाबालिग की पहचान उजागर करना अपराध है। आयोग ने सबसे अपील की कि किशोरी से जुड़े वीडियो को तुरंत हटाया जाए और इसे आगे साझा न किया जाए। उन्होंने टूटते पारिवारिक रिश्ते, घटती नैतिकता और विद्वेष को मुख्य वजह बताया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र

देहरादून। चम्पावत में कथित दुराचार प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर न्यायिक जांच कराने की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि जांच की निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए पारदर्शी और स्वतंत्र जांच कराई जानी जरूरी है।

Amar Ujala, Lucknow, 09/05/2026
Page No: 6, Size: 5.13cm × 13.47cm

मानव तस्करों की संपत्ति होगी जब्त, बैंक खाते फ्रीज होंगे

लखनऊ। राजीव कृष्ण ने मानव तस्करी रोकने के लिए प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी संगठित अपराध है, इसलिए इसमें शामिल अपराधियों पर आर्थिक कार्रवाई भी की जाएगी। डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि तस्करों और उनके सहयोगियों के बैंक खाते फ्रीज किए जाएं तथा अवैध कमाई से बनाई गईं संपत्तियां जब्त की जाएं। इसके लिए बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सिफारिशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग अभियान चलाने को भी कहा गया है। साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कर्मियों को डिजिटल अपराध और रेस्क्यू प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ब्यूरो

Source: https://medicaldialogues.in/news/education/medical-colleges/faridabads-medical-college-addresses-complaints-after-mbbs-students-protest-over-deficiencies-170234

Faridabad's medical college addresses complaints after MBBS students protest over deficiencies
Written By : Adity Saha Published On 8 May 2026 2:37 PM | Updated On 8 May 2026 2:37 PM

Faridabad: After MBBS students at Shri Atal Bihari Vajpayee Government Medical College, Chhainsa, staged a protest over severe water shortage and other infrastructure issues, the college administration has admitted to several deficiencies and said the issues are being actively addressed.

Medical Dialogues had earlier reported that the students of this institute complained of no proper access to clean drinking water, and the electricity arrangements in classrooms are inadequate. They said this has made the situation difficult, especially during the ongoing extreme heat. Due to the lack of clean water, students alleged they are forced to buy drinking water online.

These students also raised concerns about the attached hospital, claiming low patient inflow, irregular electricity supply, and lack of clean water facilities. They said that despite joining to pursue medical education, the institution lacks basic academic infrastructure. They stressed that they need a permanent solution rather than temporary arrangements.

Extending its support to these medical students, the Federation of All India Medical Association (FAIMA) wrote to the National Medical Commission (NMC) seeking urgent intervention. It stated that despite the college being approved by the NMC in 2020, with its first batch admitted in 2022, the institution has failed to meet even the most basic standards required for a functioning medical college.

In a letter to the Federation of All India Medical Association (FAIMA) issued, the Director of the institute said the institution is facing challenges as it is a newly established medical college, but remains committed to maintaining National Medical Commission (NMC) standards and ensuring quality medical education and patient care.

Regarding the severe water scarcity issue in the campus hostels, the administration stated that the shortage was caused by a damaged main water pipe, which resulted in a total lack of water for approximately 10 to 12 hours. After the Director addressed the students and provided a firm reassurance that the issue would be resolved immediately, the strike was officially called off at 02.05.2026 (01:15 AM), said the institute.

The institute said temporary water arrangements were made the same evening from 4 PM till late at night to meet students' urgent needs. It further stated that the Junior Engineer of the Public Health Engineering Department (PHED) was contacted by the institute staff and later by the Director himself, but the official allegedly refused immediate repair work, citing a delay in the release of government funds.

The administration said the damaged water pipe was permanently repaired on May 2 between 8:30 AM and 10:30 AM, after which water supply to both hostels was fully restored.

"Also, detailed inspection of Clinical, Academic and Infrastructure facilities by the DMER Headquarters Team was held on 05.05.2026, and the issues raised by the students and faculty were discussed in detail, and authorities assured that all genuine issues are being actively pursued with the competent authorities," the institution said in the letter.

Explaining the reason behind the infrastructure issues, the administration said that some issues related to electricity and water supply occurred due to wiring faults and technical limitations. For this, repair works and improvements in backup power and water supply systems are being carried out in coordination with PWD and PHED.

The students previously highlighted that at the time of admission of the first batch, even OPD services were non-

functional. While OPD services have now commenced, patient inflow remains extremely low, and IPD services continue to be non-functional, severely compromising clinical training.

On this, the institution clarified that it is still in its developmental phase, and hospital services are being expanded gradually. OPD services are fully functional, and patient inflow is increasing steadily. They said efforts are underway to strengthen IPD to improve clinical exposure for students.

Not only this, but allegations also surfaced about the unavailability of essential medicines in the hospital pharmacy, forcing patients to procure them externally. However, the institute said that medicines and consumables are being procured through government agencies, and any temporary shortages are being addressed on priority.

Addressing the shortage of faculty and academics, the medical college authorities said that faculty recruitment is in process at the State Government level.

"The institute administration has regularly taken up the matter for early filling of vacant posts and deputation of faculty from other institutes, so that patient care and academic activity is not affected. Also, the institute has MOU with BK Hospital, (Civil hospital), Faridabad for academic and patient care activities. Despite staff shortages, efforts are being made to continue academic activities smoothly and maintain teaching standards," it added.

It further stated that deficiencies pointed out during inspections are being addressed in a time-bound manner. Continuous efforts are being undertaken to further strengthen infrastructure, academics, and hospital services.

"The administration appreciates the concerns raised by students and assures that all genuine issues are being actively pursued with the competent authorities for early resolution," the letter read.

Apart from FAIMA, the United Doctors Front (UDF) also wrote to the NMC, the Ministry of Health and Family Welfare, and the National Human Rights Commission, seeking urgent intervention.

Recently, information obtained through a Right to Information (RTI) application revealed that the medical college's condition remains poor despite receiving a substantial Rs 200 crore in funding. The RTI application was filed by the Democratic Medical Association (DMA India) and it showed that since 2020, the college has received huge funding for different administrative purposes.

Source: https://www.newindianexpress.com/nation/2026/May/09/almost-500-custodial-deaths-in-seven-years-government-tells-jharkhand-hc

Nation

Almost 500 custodial deaths in seven years, government tells Jharkhand HC

The figure was revealed during the hearing of the PIL filed by Mumtaz Ansari seeking judicial inquiry into all the deaths that took place in judicial or police custody.

After hearing arguments from both sides on Thursday, the court has reserved its order.Photo| EPS

Mukesh Ranjan

Updated on: 09 May 2026, 8:11 am

RANCHI: In a major revelation before the Jharkhand High Court, the state government disclosed that nearly 500 custodial deaths have been reported in the state over the past seven years.

According to an affidavit filed by the Principal Secretary of the Department of Home, Prisons and Disaster Management, 437 deaths occurred in judicial custody while nearly 45 deaths took place in police custody since 2018.

The figure was revealed during the hearing of the PIL filed by Mumtaz Ansari seeking judicial inquiry into all the deaths that took place in judicial or police custody. After hearing arguments from both sides on Thursday, the court has reserved its order.

Filed by the state government, the affidavit further revealed that judicial inquiries could be conducted in only half of the judicial death cases. It also stated that investigations are still pending in 11 of the 42 police custody death cases.

“As per the affidavit filed by the state government, a total of 437 deaths have taken place in judicial custody while nearly 42-45 deaths have taken place in police custody.

Interestingly, judicial inquiry has been initiated in only half of the deaths taking place in police and judicial custody, which has been admitted by the state government in its affidavit,” said advocate Shadab Ansari, appearing on behalf of the petitioner. After hearing both sides, the court kept its order reserved, he added.

Advocate Ansari, appearing for the petitioner, presented written arguments in support of his case on Thursday. He contended that the nature of deaths occurring in custody can be suspicious; therefore, an impartial and high-level inquiry into these cases is imperative.

References were also made to previous orders of the Supreme Court and the guidelines issued periodically by the National Human Rights Commission (NHRC). The petitioner’s primary emphasis was on fixing accountability for any death occurring within a police station or jail, with the aim of curbing such incidents in the future.

No to judicial inquiry

The court observed that since the deaths have taken place several years back, therefore, judicial inquiry in those

cases may not be feasible, then the petitioner's advocate pleaded before the court to form guidelines for the investigation of those cases.

Source: https://avikaluttarakhand.com/uttarakhand/champawat-rape-case-congress-sends-letter-to-human-rights-commission/

Homeउत्तराखंडचंपावत दुष्कर्म प्रकरण-कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग को भेजा पत्र
उत्तराखंड
चंपावत दुष्कर्म प्रकरण-कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग को भेजा पत्र
08/05/2026 अविकल उत्तराखंड

मेडिकल रिपोर्ट समेत मामले से जुड़े मसले उठाए

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ प्रतिमा सिंह ने चम्पावत सामूहिक बलात्कार प्रकरण पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायती पत्र लिखते हुए पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराये जाने की मांग की है।

डॉ प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रकरण के मुख्य आरोपी के रूप मे सत्ताधारी दल के नेता का नाम सामने आने के उपरान्त पूरे मामले को नया रंग दिया जा रहा है। पुलिस जांच पर कई प्रकार का संदेह पैदा हो रहा है। इस हेतु सामूहिक बलात्कार की निष्पक्ष जांच कराया जाना और पीड़िता तथा उसके परिवार की सुरक्षा प्रदान किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

पत्र में कहा है कि कथित पीड़िता के 70 वर्षीय पिता जो दिव्यांग हैं तथा बिस्तर पर है। लड़की आइस क्रीम शॉप पर जॉब करती है।
पुलिस अगर बोल रही है कुछ हुआ नहीं साजिश थी फिर एफआईआर में क्या लिखा गया? मेडिकल क्यों हुआ मेडिकल में क्या निकला?

रेप पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने क्या बयान दिया? ये पुलिस ने जारी कैसे कर दिया?, एक बार एफआईआर हो गई तो पुलिस कैसे अपने निर्णय को सुना सकती है जब तक कोर्ट में मैटर ट्रायल पर नहीं जाएगा।

सीएमओ चंपावत का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल 6 मई को सुबह 7 बजे महिला चिकित्सकों द्वारा किया गया था। शरीर पर कोई चोट, संघर्ष के निशान नहीं हैं। पैरों पर रस्सी के निशान भी नहीं है। हाथ पर एक नीला निशान है जो तीन दिन पुराना है । अंदरूनी जाँच में भी कोई दुष्कर्म के साक्ष्य नहीं है।
सीएमओ ने बताया हमने जाँच के किए स्वाब सैंपल, कपड़ों की जाँच के बाद उन्हें सील करके पुलिस को दिया है।

जबकि नाबालिग पीड़िता के पिता की तहरीर के अनुसार पीड़िता पर हथियार से दबाव बनाया गया था ।
कई बार धमकी, डर और दिए गए नशे के कारण पीड़ित संघर्ष नहीं कर पाता और शायद इसलिए शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं मिलते, इसका मतलब यह नहीं की दुष्कर्म नहीं है। इसको लेकर कोर्ट के आदेशों में क्लियर गाइडलाइंस हैं।
क्या महिला चिकित्सकों ने नाबालिग पीड़िता से पूछताछ की? की कब क्या क्या हुआ? क्या मजिस्ट्रेट और महिला चिकित्सकों के सामने पीड़िता के बयान मेल खाते हैं? क्या नाबालिग पीड़िता बयान देने की स्थिति में थी? यह सवाल हमेशा राज रहेगा कि नाबालिग पीड़िता के पिता और भाई ने जो लिखा है वो क्या था? क्या एक 70 साल का बीमार व्यक्ति भी साजिश में शामिल हो सकता है?

क्या एक लड़की जो मेहनत करके अपने पिता का इलाज करवा रही है और पढ़ाई भी कर रही है वह प्रलोभन में आ सकती है की इतना बड़ा नाटक रच दे? यह जानते हुए की सच सामने आ गया तो समाज बहिष्कार भी कर सकता है, क्या इतनी बड़ी साजिश रच सकती है?

डॉ प्रतिमा सिंह ने मांग की है कि चम्पावत प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाय जिससे प्रदेश में बढते महिला अपराधों पर अंकुश लग सके।

Source: https://www.amarujala.com/lucknow/up-strict-instructions-issued-regarding-human-trafficking-property-of-accused-to-be-confiscated-bank-accoun-2026-05-08?src=top-subnav-amp

यूपी: मानव तस्करी को लेकर सख्त निर्देश जारी, आरोपियों की संपत्ति की जाएगी जब्त; फ्रीज होंगे बैंक खाते

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 08 May 2026 08:37 PM IST

सार

Human trafficking in UP: यूपी में मानव तस्करी के आरोपियों को लेकर सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने निर्देश जारी किए हैं।

विस्तार

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मानव तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने और इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पत्र प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को जारी किया गया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।

डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, इसलिए अब तस्करों पर आर्थिक प्रहार भी किया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि मानव तस्करी में शामिल अपराधियों और उनके सहयोगियों के बैंक खाते फ्रीज किए जाएं और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाए। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जनता को जागरूक भी करें

डीजीपी ने सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठन, रेलवे पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और श्रम विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान चलाने को कहा गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) और मिशन शक्ति केंद्रों से जुड़े कर्मियों को डिजिटल अपराध, रेस्क्यू प्रोटोकॉल और प्रभावी विवेचना का प्रशिक्षण भी देने को कहा गया है।

रिश्वत ली तो सख्त कार्रवाई

पत्र में कहा गया है कि पासपोर्ट, वीजा आदि के बदले रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों, बिचौलियों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरह की लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

Source: https://medicaldialogues.in/news/education/medical-colleges/rti-reveals-rs-200-crore-funding-to-faridabads-medical-college-amid-infrastructure-row-170198

RTI reveals Rs 200 crore funding to Faridabad's medical college amid infrastructure row
Written By : Barsha Misra Published On 8 May 2026 11:20 AM | Updated On 8 May 2026 11:20 AM

Faridabad: Amid the ongoing controversy and allegations of inadequate infrastructure at Shri Atal Bihari Vajpayee Government Medical College, Faridabad, information obtained through a Right to Information (RTI) application has revealed that the medical college's condition remains poor despite receiving a substantial Rs 200 crore in funding.

The RTI application was filed by the Democratic Medical Association (DMA India) and it showed that since 2020, the college has received huge funding for different administrative purposes.

Referring to the RTI information, the National President of DMA, Dr. Amit Vyas, said, "In a shocking revelation through an RTI filed by the DMA, it has come to light that Dr. Vyas pointed out that the institute lacks basic facilities that are considered essential for any healthcare and educational institution, including- reliable power backup system, separate academic and hospital buildings, adequate stock of essential medicines and equipment, adequate drinking water facilities for students, etc. Allegedly, the students also have to face frequent power cuts due to faulty wiring and completely deteriorated sanitation system.

"When such a large amount of public money has been spent without visible improvement on the ground, it not only reflects systemic failure but also raises serious concerns about possible corruption," he said.

Terming this 'a major failure of the Haryana Government,' the doctor stated that all relevant documents and evidence related to this matter will be submitted to the State Anti-Corruption Bureau. This includes- where and how the Rs 200 crore budget was utilised, and which officials or responsible individuals may be involved.

Dr. Vyas further mentioned that if strict and transparent action is not taken promptly, the organization will be compelled to escalate the issue at a larger level. "This is not just about one institution, but about the credibility of the entire healthcare system," he added.

Medical Dialogues had earlier reported how the students of this institute complained of no proper access to clean drinking water and that the electricity arrangements in classrooms are inadequate. They said this has made the situation difficult, especially during the ongoing extreme heat. Due to the lack of clean water, students alleged they are forced to buy drinking water online. They stressed that they need a permanent solution rather than temporary arrangements.

Apart from this, students also raised concerns about the hospital attached to the college. They claimed that there are no patients, irregular electricity supply, and no proper clean water facility. They added that while they came to study, the institution lacks basic academic infrastructure.

Recently, extending its support to these medical students, the Federation of All India Medical Association (FAIMA) wrote to the National Medical Commission (NMC) seeking urgent intervention. It stated that despite the college being approved by the NMC in 2020, with its first batch admitted in 2022, the institution has failed to meet even the most basic standards required for a functioning medical college.
Meanwhile, expressing concern over the alleged poor and unsafe living conditions of medical students at Shri Atal Bihari Vajpayee Government Medical College, the United Doctors Front (UDF) wrote to the NMC, the Ministry of Health and Family Welfare, and the National Human Rights Commission, seeking urgent intervention.

Dainik Bhaskar, Online News, 09/05/2026

Source:
https://www.bhaskar.com/local/uttarakhand/dehradun/news/champawat-police-probe-political-influence-pramita-singh-nhrc-137885793.html

चंपावत मामले पर कांग्रेस का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र:पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे गंभीर सवाल, प्रतिमा सिंह बोलीं-सत्ता से जुड़े नेता का नाम आते ही बदला केस
देहरादून16 घंटे पहले

चंपावत की तथाकथित घटना को लेकर अब सियासत और तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. प्रमिता सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई है। कांग्रेस का आरोप है कि मामले में सत्ताधारी दल से जुड़े नेता का नाम सामने आने के बाद जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस की कहानी पर उठ रहे गंभीर सवाल-प्रतिमा सिंह

डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि पुलिस की जांच और बयानों में कई विरोधाभास नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस का दावा है कि मामला 'साजिश' था और कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर एफआईआर में क्या लिखा गया। पीड़िता का मेडिकल क्यों कराया गया। मजिस्ट्रेट के सामने क्या बयान दर्ज हुए और जांच पूरी होने से पहले पुलिस किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गई।

कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा गया पत्र
कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएमओ चंपावत के उस बयान पर भी सवाल खड़े किए, जिसमें कहा गया कि पीड़िता के शरीर पर संघर्ष या दुष्कर्म के स्पष्ट निशान नहीं मिले। डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार हर दुष्कर्म में शारीरिक चोट होना जरूरी नहीं होता। कई बार डर, धमकी या नशे की स्थिति में पीड़िता विरोध नहीं कर पाती, इसलिए केवल चोट के निशान न मिलने से घटना को झूठा नहीं कहा जा सकता।

क्या एक बीमार पिता साजिश रच सकता है-प्रतिमा

उन्होंने कहा कि पीड़िता के 70 वर्षीय दिव्यांग पिता, जो बिस्तर पर हैं, आखिर क्यों ऐसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया कि मेहनत करके परिवार चलाने वाली और पढ़ाई कर रही एक नाबालिग लड़की आखिर क्यों अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर इतना बड़ा आरोप लगाएगी। डॉ. प्रतिमा सिंह ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए और पीड़िता व उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों को देखते हुए इस मामले की पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है, ताकि सच सामने आ सके और लोगों का कानून पर भरोसा बना रहे।

Source: https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam/muslim-news/national-human-rights-commission-has-closed-ongoing-case-against-journalist-omar-rashid/3209063

Zee SalaamIndian MuslimNHRC ने पत्रकार उमर राशिद केस में जांच की बंद, दिल्ली पुलिस को नहीं मिला सबूत
NHRC ने पत्रकार उमर राशिद केस में जांच की बंद, दिल्ली पुलिस को नहीं मिला सबूत
Omar Rashid Case: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्रकार उमर राशिद के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया है. दिल्ली पुलिस की जांच में सोशल मीडिया पर लगाए गए गुमनाम आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद आगे कार्रवाई नहीं की गई.

Written By Tauseef Alam|Last Updated: May 08, 2026, 09:54 AM IST

Omar Rashid Case: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पत्रकार उमर राशिद के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया है. यह मामला पिछले लगभग 300 दिनों से लंबित था और सोशल मीडिया पर लगाए गए गुमनाम आरोपों के आधार पर शुरू की गई जांच अब समाप्त कर दी गई है.

दरअसल, साल 2025 में सोशल मीडिया पर कुछ गुमनाम पोस्ट सामने आए थे, जिनमें उमर राशिद पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. इन पोस्टों के आधार पर सह्याद्री राइट्स फोरम से जुड़े तामीर एन नामक व्यक्ति ने NHRC में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत मिलने के बाद आयोग ने 23 मई 2025 को मामला दर्ज करते हुए दिल्ली पुलिस को जांच का निर्देश दिया था.

साल 2005 दिल्ली पुलिस ने सौंपी थी रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के बाद 6 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी. रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि मामले में आगे कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं मिला. पुलिस के मुताबिक, कथित पीड़िता ने न तो अपनी पहचान सार्वजनिक की और न ही अपना पता उपलब्ध कराया. इसके अलावा उसने जांच को आगे बढ़ाने में भी कोई रुचि नहीं दिखाई. पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायत पूरी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुए गुमनाम आरोपों पर आधारित थी. जांच के दौरान उन पोस्टों और आरोपों की समीक्षा की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत या सत्यापित की जा सकने वाली जानकारी सामने नहीं आई.

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से भी जांच के दौरान किसी तरह का अतिरिक्त सहयोग नहीं मिला. पुलिस की रिपोर्ट या आगे की प्रक्रिया पर शिकायतकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया. ऐसे में जांच एजेंसियों को आगे कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला. इसी रिपोर्ट के आधार पर NHRC ने अब मामले को बंद करने का फैसला लिया है. आयोग ने माना कि उपलब्ध तथ्यों और पुलिस जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जरूरत नहीं है. उमर राशिद उस समय एक प्रमुख न्यूज़ एजेंसी से जुड़े हुए थे और मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी बहस भी हुई थी.

Source: https://hyderabadmail.com/secunderabad-delivery-worker-police-assault-nhrc-complaint/

Hyderabad
NHRC complaint filed after alleged assault on Hyderabad delivery worker
Durga Prasad Sunku 8 May 2026 1:19 PM

HYDERABAD: A delivery partner was allegedly assaulted by police in Secunderabad early Thursday morning. The incident has raised concerns about the safety of app-based delivery workers and prompted the Telangana Gig and Platform Workers Union (TGPWU) to approach the National Human Rights Commission (NHRC).
Geographic Reference
Shabbir Azam, a Falaknuma resident and delivery worker since 2018, was assigned an ice cream delivery from Scope Ice Cream in Secunderabad at 2:50 AM on May 7, 2026. While waiting to collect the order, two constables from Ramgopalpet Police Station reportedly arrived and began verbally abusing the delivery workers.

Subsequently, according to a complaint filed with the NHRC by TGPWU founder president Shaik Salauddin, the situation escalated when the Station House Officer (SHO) of Ramgopalpet Police Station arrived and allegedly began physically assaulting Azam.
"He was slapped, abused, and beaten with a lathi without any provocation," the complaint states. When shop manager Rahil Hussain stepped outside to explain the establishment had permission to operate, he was also allegedly beaten and abused by the SHO.

Azam reportedly tried to show his order details in the Swiggy app to prove he was on duty, but the assault continued.
In his representation to the NHRC, Salauddin emphasized that this incident is not isolated. "There have been repeated complaints from gig and app-based delivery workers across Hyderabad about harassment, illegal detention, verbal abuse, intimidation, and physical violence by police during night shifts," the complaint notes.
Geographic Reference
The union noted that delivery workers are not responsible for whether restaurants or shops operate at night. Aggregator companies assign orders only when establishments are open. Furthermore, "Delivery workers merely transport food and essential goods to customers. They are among the most economically vulnerable urban workers," the complaint adds.
The TGPWU alleged that the police actions violated the right to life and dignity under Article 21 of the Constitution, abused police power, humiliated workers engaged in lawful employment, intimidated vulnerable gig workers, and violated basic human rights and labor dignity.

In this context, the union urged the NHRC to take suo motu cognizance of the incident and order an independent inquiry into the conduct of the SHO and police at Ramgopalpet Police Station. They also requested disciplinary and legal action against responsible officers, protection and compensation for Shabbir Azam, and clear guidelines to prevent harassment and violence against delivery workers during night duty.
The incident has renewed focus on the precarious working conditions of India's growing gig workforce. Moreover, the union stated that night-time workers are particularly vulnerable to police violence, arbitrary checks, extortion, and abuse.

"Such incidents create fear and insecurity among thousands of workers who depend on these jobs for survival," the complaint noted, especially during extreme summer conditions when nighttime deliveries increase.

Source: https://www.siasat.com/video-shows-hyderabad-police-assaulting-delivery-worker-nhrc-complaint-filed-3467671/amp/

Hyderabad
Video shows Hyderabad police assaulting delivery worker, NHRC complaint filed
TGPWU files complaint with NHRC after viral video allegedly shows Ramgopalpet Police assaulting Swiggy delivery worker Shabbir Azam during night duty in Hyderabad.
May 8, 2026 5:10 pm

Hyderabad: A video allegedly showing Hyderabad police personnel assaulting a Swiggy delivery worker during night duty in Secunderabad has sparked outrage on social media, with the Telangana Gig and Platform Workers Union (TGPWU) accusing the police of targeting app-based workers.
The video, shared by TGPWU on X, purportedly captures a confrontation involving delivery workers and personnel from Ramgopalpet Police Station during the early hours of May 7.

The union strongly condemned the incident, stating that “gig workers are earning livelihoods, not committing crimes,” and demanded an end to violence and intimidation against app-based workers.
NHRC complaint filed
Following the circulation of the video, the union filed a complaint before the National Human Rights Commission (NHRC), seeking action against the police personnel involved.

According to the complaint, the incident took place around 2:50 a.m. when Shabbir Azam, a delivery worker from Falaknuma, arrived at an ice cream shop in Secunderabad to collect an order assigned through the Swiggy app. The establishment falls under the jurisdiction of the Mahankali Police Station.

TGPWU alleged that police personnel began questioning and verbally abusing delivery workers gathered outside the shop. When Azam attempted to explain that he was on active duty and showed the delivery details on his phone, the Station House Officer (SHO) allegedly assaulted him and beat him with a lathi without provocation.

The complaint further alleged that the shop manager, Rahul Hussain, was also beaten after intervening and informing the officers that the establishment had permission to remain open during night hours.

Describing the incident as part of a wider pattern of harassment faced by gig workers during night shifts, the union said app-based delivery personnel are routinely subjected to intimidation, abuse, and arbitrary policing despite providing essential services.

TGPWU seeks independent inquiry
In its representation to the NHRC, TGPWU sought an independent inquiry into the incident, disciplinary and legal action against the officers involved, compensation for the victim, and guidelines to prevent harassment of gig and platform workers during night duty.

Source: https://avenuemail.in/nhrc-seeks-report-jharkhand-remand-home-death-deoghar/

CrimeJharkhandNews
NHRC Seeks Report from Jharkhand Govt On Suspicious Death at Deoghar Remand Home
By News Desk Friday, 8 May 2026, 12:51:55 IST

The NHRC has issued notices to the Jharkhand government over the suspicious death of a 19-year-old inmate at a Deoghar remand home, the fifth death at the facility this year
New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has directed the Jharkhand government and the Deoghar police to submit a detailed report within two weeks regarding the death of a 19-year-old female inmate. The woman, an inhabitant of a remand home in the Charki Pahadi area, died on May 2 under suspicious circumstances.

Suo Motu Cognizance
Taking suo motu cognizance of media reports, the NHRC observed that the incident indicates a serious violation of human rights. The Commission issued formal notices to the Chief Secretary of Jharkhand and the Superintendent of Police, Deoghar.

The inmate reportedly fell ill suddenly at the facility and died while undergoing treatment at Deoghar Sadar Hospital. While the official cause of death remains unconfirmed, the incident has highlighted alarming trends at the facility; five inmates have reportedly died at this specific remand home since January 1, 2026.

Sewer Deaths in Haryana
In a separate intervention, the NHRC took cognizance of the deaths of two sanitation workers in Greater Faridabad, Haryana. The workers died on May 2 while cleaning a sewer at a residential society. Reports indicate the workers entered the manhole without gas masks or protective gear under the instructions of the estate manager.

The Commission has asked the Faridabad Municipal Commissioner and the Commissioner of Police for a report on the investigation status and compensation for the victims' families. The NHRC expressed concern that such fatalities persist despite Supreme Court guidelines and national advisories mandating mechanized cleaning and safety equipment for sanitation staff.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/food-delivery-worker-alleges-police-assault-gig-workers-union-writes-to-nhrc/articleshow/130966148.cms

Food delivery worker alleges police assault; gig workers union writes to NHRC
Mahesh Buddi / Updated: May 09, 2026, 07:34 IST

HYDERABAD: The Telangana Gig and Platform Workers Union (TGPWU) has written to the National Human Rights Commission of India (NHRC) after CCTV footage showing Ramgopalpet police allegedly assaulting a delivery worker for a quick-commerce platform during the early hours of Thursday surfaced online.

In a letter addressed to NHRC chairperson Justice V Ramasubramanian, TGPWU founder-president SK Salauddin alleged that Hyderabad police assaulted and harassed delivery worker Shabbir Azam, a resident of Falaknuma, at around 2.50 am on May 7.

According to the complaint, Azam was waiting to pick up an ice cream order from a store in Secunderabad when two police constables from Ramgopalpet police station arrived and instructed the delivery workers gathered there to leave. "When Shabbir Azam attempted to explain and show the order details assigned through the application, the station house officer (SHO) of Ramgopalpet police station physically assaulted him without any provocation. The shop manager, Rahil Hussain, attempted to explain that the establishment had permission to operate. However, he too was beaten and abused by the SHO, Salauddin stated in the complaint submitted to the NHRC.

Meanwhile, Ramgopalpet inspector B Suresh Kumar told TOI that the store was operating beyond permitted hours. "The permission for the store to operate till the early hours had expired in 2024. I was on night patrol and found the shop open and delivering orders even after 3 am. One of the persons standing outside the shop, who was not in uniform, responded in a rude and objectionable manner when asked to leave and created a nuisance. I had to use mild force to disperse him," the inspector said.

Mahankali police later registered two petty cases one against Azam for alleged nuisance and another against the shop manager for operating the business beyond permitted hours.

Hindustan Times, Delhi, 09/05/2026
Page No: 6, Size: 9.15cm × 7.41cm

NHRC TAKES NOTE OF 19 PUPILS CONTRACTING TB IN SHIMLA

The National Human Rights Commission (NHRC), India, took suo motu cognisance of a media report that 19 female students were infected with tuberculosis in the hostel of the MGMSC Nursing College, Shimla, Himachal Pradesh.

Hindustan Times, Delhi, 09/05/2026
Page No: 6, Size: 9.08cm × 13.94cm

NHRC Takes Cognisance of Death of an Inmate

The National Human Rights Commission (NHRC), India took suo motu cognisance of a media report about the death of a 19-year-old female inmate of a Remand Home in the Charki Pahadi area of the Deoghar district of Jharkhand on May 2, 2026, under suspicious circumstances. The cause of her death is yet to be ascertained. The commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

Morning Standard, Delhi, 09/05/2026
Page No: 8, Size: 9.53cm × 17.49cm

Almost 500 custodial deaths in seven years, govt tells J'khand HC

MUKESH RANJAN @ Ranchi

IN a major revelation before the Jharkhand High Court, the state government disclosed that nearly 500 custodial deaths have been reported in the state over the past seven years.

According to an affidavit filed by the Principal Secretary of the Department of Home, Prisons and Disaster Management, 437 deaths occurred in judicial custody while nearly 45 deaths took place in police custody since 2018. The figure was revealed during the hearing of the PIL filed by Mumtaz Ansari seeking judicial inquiry into all the deaths that took place in judicial or police custody. After hearing arguments from both sides on Thursday, the court has reserved its order.

Filed by the state government, the affidavit further revealed that judicial inquiries could be conducted in only half of the judicial death cases. It also stated that investigations are still pending in 11 of the 42 police custody death cases. "As per the affidavit filed by the state government, a total of 437 deaths have taken place in judicial custody while nearly 42-45 deaths have taken place in police custody. Interestingly, judicial inquiry has been initiated in only half of the deaths taking place in police and judicial custody, which has been admitted by the state government in its affidavit," said advocate Shadab Ansari, appearing on behalf of the petitioner. After hearing both sides, the court kept its order reserved, he added.

Advocate Ansari, appearing for the petitioner, presented written arguments in support of his case on Thursday. He contended that the nature of deaths occurring in custody can be suspicious; therefore, an impartial and high-level inquiry into these cases is imperative.

References were also made to previous orders of the Supreme Court and the guidelines issued periodically by the National Human Rights Commission (NHRC). The petitioner's primary emphasis was on fixing accountability for any death occurring within a police station or jail, with the aim of curbing such incidents in the future.

No to judicial inquiry

The court observed that since the deaths have taken place several years back, therefore, judicial inquiry in those cases may not be feasible, then the petitioner's advocate pleaded before the court to form guidelines for the investigation of those cases.